

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय

पूर्ण बेंच

*न्यायमूर्ति* हरबंस सिंह, *न्यायमूर्ति* डी.के. महाजन और *न्यायमूर्ति* एस. एस. संधवालिया, के *समक्ष*

मदन तरलोक सिंह और अन्य, याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ और अन्य, उत्तरदाता

1968 की सिविल रिट संख्या 3759

28 अप्रैल, 1970

भारत का संविधान - अनुच्छेद 276, सूची I की प्रविष्टि 82 और अनुसूची VII की सूची II की प्रविष्टि 60 - अनुच्छेद 276 की प्रयोज्यता के लिए सीमाओं का दायरा - कहा गया है।

पंजाब व्यवसाय, व्यापार, कॉलिंग और रोजगार कराधान अधिनियम (1956 का VII) - चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के लिए प्रयोज्यता - चाहे वह अनुच्छेद 276 द्वारा प्रभावित हो - अधिनियम - चाहे वह अधिकार हीन हो।

**और रूप:**

(बहुमत के अनुसार हरबंस सिंह और एसएस संधवालिया, जेजे महाजन, जे. कॉन्ट्रा), कि भारत के संविधान की अनुसूची VII की सूची I के अनुच्छेद 276 और प्रविष्टि 82 और सूची II की प्रविष्टि 60 को अलग-अलग अधिकारियों द्वारा एक ही हाथ में एक ही आय के कई करों के खिलाफ कुछ सुरक्षा उपायों को सुरक्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस प्रकार इस तरह के दोहरे कराधान की घटनाओं और मात्रा दोनों को सीमित दायरे में रखने का प्रयास किया जाता है। यह स्पष्ट है कि संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I और II कराधान की शक्तियों से बचते हैं और भारत संघ और राज्यों के लिए कराधान के पर्याप्त स्रोतों को आवंटित करने के आधार पर आगे बढ़ते हैं, जिसका उद्देश्य दोनों के बीच परस्पर विरोधी या प्रतिस्पर्धी कराधान शक्तियों की समस्याओं को सीमित करना है। सूची-I की प्रविष्टि 82 में यह स्पष्ट किया गया है कि कृषि आय के अलावा अन्य आय पर केवल संसद ही कर

लगाने की हकदार है। राज्य विधानमंडल भारत के संविधान के अनुच्छेद 276 द्वारा लगाए गए संकीर्ण सीमाओं के भीतर उस क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं कर सकता है और इस अनुच्छेद के अपवाद की प्रकृति में होने के खिलाफ होने के कारण जिस विषय को कई कराधान के खिलाफ संरक्षित करने की मांग की जाती है, उसे सख्ती से समझा जाना चाहिए और राज्य विधानमंडल को उसी आय पर कर लगाने के क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले उसमें रखी गई सभी अपेक्षित शर्तों को पूरी तरह से संतुष्ट किया जाना चाहिए।

(पैरा 18 और 19)

*और रूप:*

संविधान के अनुच्छेद 276 की भाषा इसकी प्रयोज्यता के लिए तीन स्पष्ट सीमाओं को बताती है। पहली सीमा कराधान के विषय के संबंध में है और इसमें यह निर्धारित किया गया है कि बचाए जाने वाले प्रासंगिक कर को व्यवसायों, व्यापारों, कॉलिंग और रोजगारों के संबंध में होना चाहिए। दूसरे, कर की मात्रा पर एक सीमा लगाई गई है और यह निर्धारित किया गया है कि ऐसा कर प्रति वर्ष 250 रुपये से अधिक नहीं होगा। तीसरी सीमा इस तरह के कर लगाने के उद्देश्य से संबंधित है, अर्थात्, यह राज्य या नगर पालिका, जिला बोर्ड, स्थानीय बोर्ड या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के आर्थिक लाभ के लिए एक कर होना चाहिए। यदि ये तीनों शर्तें पूरी हो जाती हैं तो केवल एक राज्य द्वारा लगाई गई आय पर कर अनुच्छेद 276 की स्पष्ट शर्तों द्वारा अमान्य होने से बचाया जाता है।

(पैरा 20)

*और रूप:*

उस संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ की अपनी कोई वित्तीय पहचान नहीं है। पंजाब व्यवसाय, व्यापार, कॉलिंग और रोजगार कराधान अधिनियम, 1956 के तहत लगाए गए कर की पूरी

आय सीधे भारत की संचित निधि में जाती है। इसका कोई भी हिस्सा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के किसी अलग खजाने में नहीं जाता है। इस राशि की कोई अलग पहचान या खाता नहीं रखा जाता है जब इसे भारत की संचित निधि में जमा किया जाता है। एक बार जब यह भारत की संचित निधि में जमा हो जाता है, तो इसकी अभिरक्षा, नियंत्रण और विनियोग भारत संघ में निहित होता है। इस सब के आलोक में, इसलिए, यह संभवतः नहीं कहा जा सकता है कि अधिनियम के तहत लगाया गया कर केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के राजस्व के लाभ के लिए है। सर्वोच्च शर्त अनुच्छेद 276 की आवश्यकता की संतुष्टि है कि कर लगाने वाले राज्य के राजस्व के लाभ के लिए कर होना चाहिए और जब तक ऐसा नहीं किया जाता है) असंवैधानिकता की बुराई को ऐसे कानून से जोड़ना जारी रखना चाहिए। इसलिए यह अधिनियम केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के लिए अपनी प्रयोज्यता में संविधान के अनुच्छेद 276 के तहत स्पष्ट रूप से बाहर है।

(पैरा 25, 27 और 29)

और रूप:

पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के तहत केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का प्रशासन केंद्र सरकार के पास है और केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में संसद द्वारा वैध रूप से पारित कानून को केवल इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की कोई समेकित निधि नहीं है। अनुच्छेद 276 कानून लागू करने वाले राज्य या क्षेत्र की संचित निधि में जमा किए जाने वाले कर की बात नहीं करता है। इसके अलावा, अनुच्छेद में "राज्य या नगर पालिका, जिला बोर्ड, स्थानीय बोर्ड या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के लाभ के लिए कर" अभिव्यक्ति केवल इस बात पर जोर देती है कि राज्य के पास कर लगाने की शक्ति है, सभी कर इसके लाभ के लिए लगाए जाते हैं। अनुच्छेद 276 का उद्देश्य ऐसे करों को संवैधानिक रूप से अमान्य होने से बचाना था क्योंकि ये कर वास्तव में आय पर कर हैं और इसलिए, राज्य विधायिका शक्ति के दायरे में नहीं हैं। केवल संसद को ही आय पर कर लगाने का अधिकार है। अनुच्छेद में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि राज्य या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा इस प्रावधान के अनुसरण में एकत्र किए गए कर को उन लोगों के लाभ के लिए खर्च किया जाना चाहिए जो इसका भुगतान करते हैं या उस क्षेत्र के निवासियों के लाभ के लिए जिसमें इसे एकत्र किया जाता है। जाहिर है, सभी करों को एक उद्देश्य के लिए एकत्र किया जाता है - उद्देश्य प्रशासन चलाना और नागरिकों के लिए अन्य लाभकारी उपाय प्रदान करना। इसलिए केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के लिए इसकी प्रयोज्यता में अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 276 के विपरीत नहीं है।

(पैरा 7, 9 और 10)

माननीय न्यायमूर्ति हरबंस सिंह और माननीय न्यायमूर्ति एसएस संधवालिया द्वारा 21 नवंबर, 1969 को मामले में शामिल कानून के एक महत्वपूर्ण पहलू के निर्णय के लिए एक बड़ी पीठ को मामला सौंपा गया। इस मामले का निर्णय 28 अप्रैल, 1970 को माननीय न्यायमूर्ति हरबंस सिंह, माननीय न्यायमूर्ति डीके महाजन और माननीय न्यायमूर्ति एसएस संधवालिया की एक बड़ी पीठ द्वारा किया गया था।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत याचिका में प्रार्थना की गई है कि सर्वोच्च न्यायालय की प्रकृति में एक रिट या कोई अन्य उचित रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए जो याचिकाकर्ताओं के पेशेवर कर लगाने के मूल्यांकन को रद्द करता है और प्रतिवादियों को उनके वेतन बिलों से कटौती की वसूली करने से रोकता है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से एडन एचएल बंसल ने पैरवी की।

उत्तरदाताओं की ओर से वकील सीडी दीवान और एसके जैना।

### निर्णय

**न्यायमूर्ति महाजन**, - यह आदेश 1968 की सिविल रिट याचिका संख्या 3759 और 1969 की 470 का निपटारा करेगा। इन दोनों मामलों को हरबंस सिंह और एसएस संधवालिया जेजे द्वारा पूर्ण पीठ को भेजा गया था। इस प्रकार इन मामलों को निपटान के लिए हमारे समक्ष रखा गया है।

(2) प्रारंभ में, खंडपीठ के समक्ष तीन बिंदुओं का आग्रह किया गया था, अर्थात् :-

(1) पंजाब व्यवसायों की प्रस्तावना को ध्यान में रखते हुए ट्रेड, कॉलिंग और रोजगार कराधान अधिनियम, 1956, (1956 का पंजाब अधिनियम संख्या 7), (इसके बाद व्यवसाय कर अधिनियम के रूप में संदर्भित), अधिनियम केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ पर लागू नहीं होता है, क्योंकि प्रस्तावना में अनुकूलन आदेश द्वारा कोई बदलाव नहीं किया गया है; और अधिनियम केवल पंजाब के क्षेत्रों पर लागू होता है;

(2) यह अधिनियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 276 को ध्यान में रखते हुए चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के गठन की तारीख से संविधान के दायरे से बाहर हो गया है; और इसलिए, किसी भी व्यापार, कॉलिंग या पेशे में लगे व्यक्तियों पर कोई कर नहीं लगाया जा सकता है;

और

(3) कि उच्च न्यायालय के कर्मचारी किसी राज्य के अधीन या किसी स्थानीय प्राधिकरण आदि के अधीन सेवा नहीं कर रहे हैं और इसके परिणामस्वरूप व्यवसाय कर अधिनियम की धारा 7 और उक्त अधिनियम के तहत बनाए गए नियम 8 उन पर लागू नहीं होते हैं और

यह वसूली उनके वेतन बिलों से कटौती से प्रभावित नहीं हो सकती है, जैसा कि उपर्युक्त नियम में प्रावधान है; और यह कि यदि कर वसूली योग्य है, तो इसे केवल नियम 9 में प्रदान किए गए तरीके से पुनर्प्राप्त किया जा सकता है।

पहली दो दलीलें दोनों याचिकाओं के लिए समान हैं और तीसरा विवाद केवल 1968 की सिविल रिट संख्या 3759 में उत्पन्न होता है, जिसे उच्च न्यायालय के कर्मचारियों द्वारा दायर किया गया है।

(3) इन विवादों से निपटने से पहले, प्रारंभिक तथ्यों को निर्धारित करना आवश्यक होगा: व्यवसाय कर अधिनियम वर्ष 1956 में पंजाब विधानमंडल द्वारा पारित किया गया था। इस अधिनियम को भारत के संविधान के अनुच्छेद 276 के प्रावधानों के मद्देनजर पंजाब विधानमंडल द्वारा पारित किया गया था, जिसे भारत के संविधान की प्रविष्टि संख्या 60, सूची II, अनुसूची सातवीं के साथ पढ़ा जाता है। बाद की घटनाओं के कारण ही वर्तमान विवाद उत्पन्न हुआ है। पूर्ववर्ती पंजाब राज्य, जैसा कि यह 1966 से पहले अस्तित्व में था, को पुनर्गठित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप, इसके क्षेत्रों का हिस्सा हिमाचल प्रदेश में स्थानांतरित कर दिया गया था; इसके क्षेत्रों के एक अन्य हिस्से ने हरियाणा के एक नए राज्य का गठन किया और चंडीगढ़ के आसपास के कुछ क्षेत्रों और चंडीगढ़ शहर सहित चंडीगढ़ को चंडीगढ़ के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में घोषित किया गया। यह पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (इसके बाद पुनर्गठन अधिनियम के रूप में संदर्भित) द्वारा प्रभावित किया गया था, यह अधिनियम 1 नवंबर, 1966 को लागू हुआ था।

इस अधिनियम को दस भागों में विभाजित किया गया है। भाग II पंजाब राज्य के पुनर्गठन से संबंधित है और भाग X, जिसके साथ हम संबंधित हैं, कानूनी और विविध प्रावधानों से संबंधित है। इस भाग में प्रासंगिक प्रावधान धारा 87, 88, 89 और 90 हैं। संदर्भ सुविधा के लिए इन प्रावधानों को नीचे प्रस्तुत किया गया है -

87. *चंडीगढ़ को अधिनियमों का विस्तार करने की शक्ति*—केंद्र सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे प्रतिबंधों या संशोधनों के साथ, जो वह उचित समझे, चंडीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र में किसी भी अधिनियमन का विस्तार कर सकती है जो अधिसूचना की तारीख पर किसी राज्य में लागू है।

88. *कानूनों की प्रादेशिक सीमा*—भाग-II के उपबंधों को उन क्षेत्रों में कोई परिवर्तन करने वाला नहीं समझा जाएगा जिन पर नियत दिन से ठीक पहले लागू कोई विधि लागू होती है और पंजाब राज्य के लिए ऐसी किसी विधि में प्रादेशिक संदर्भ, जब तक कि किसी सक्षम विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन्यथा उपबंधित न किया जाए, का अर्थ उस राज्य के भीतर के क्षेत्रों से नियत दिन से ठीक पहले लगाया जाए।

89. कानूनों को अनुकूलित करने की शक्ति।-नियत दिन से पहले बनाई गई किसी विधि के पंजाब या हरियाणा राज्य या संघ राज्य क्षेत्र हिमाचल प्रदेश या चंडीगढ़ के संबंध में आवेदन को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से, उपयुक्त सरकार, उस दिन से दो वर्ष की समाप्ति से पहले, आदेश द्वारा, कानून के ऐसे अनुकूलन और संशोधन कर सकती है, चाहे निरसन या संशोधन के माध्यम से, जो आवश्यक या समीचीन हो और उसके बाद ऐसा प्रत्येक कानून इस प्रकार किए गए अनुकूलन और संशोधनों के अधीन प्रभावी होगा जब तक कि सक्षम विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिवर्तित, निरसित या संशोधित नहीं किया जाता है।

*खुलासा।* इस खंड में, 'उपयुक्त सरकार' शब्द का अर्थ है-

(a) संघ सूची, केन्द्रीय सरकार में प्रगणित विषय से संबंधित किसी विधि का सम्बन्ध है; और

(ख) जहां तक किसी अन्य कानून का संबंध है,

(i) किसी राज्य, राज्य सरकार को इसके आवेदन में और (ii) किसी संघ राज्य क्षेत्र को इसके आवेदन में, केन्द्रीय सरकार।

90. कानूनों का निर्माण करने की शक्ति।(1) धारा 89 के अधीन कोई उपबंध या अपर्याप्त उपबंध किए जाने के बावजूद, नियत दिन से पहले बनाई गई विधि के अनुकूलन के लिए, ऐसा विधि लागू करने के लिए अपेक्षित या अधिकार प्राप्त कोई न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकारी, पंजाब या हरियाणा राज्य या हिमाचल प्रदेश या चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अपने आवेदन को सुकर बनाने के प्रयोजन से, पदार्थ को प्रभावित किए बिना, कानून को इस तरह से बनाना जो अदालत, ट्रिब्यूनल या प्राधिकरण के समक्ष मामले के संबंध में आवश्यक या उचित हो सकता है।

(2) किसी विधि में पंजाब उच्च न्यायालय के प्रति किसी भी संदर्भ का, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, नियत दिन से और उसके बाद पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के संदर्भ के रूप में अर्थ लगाया जाएगा।

(4) याचिका, जो पुनर्गठन के बाद उभरती है, यह है कि इसके पुनर्गठन से पहले पंजाब राज्य में प्रचलित कानून पुनर्गठित क्षेत्रों, अर्थात् हिमाचल प्रदेश को हस्तांतरित क्षेत्रों पर लागू रहने थे; केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में घोषित क्षेत्र, हरियाणा राज्य बनाने वाले क्षेत्र; और अविभाजित पंजाब के बाकी हिस्से में। इस प्रकार, व्यवसाय कर अधिनियम संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में लागू हो गया। चंडीगढ़ प्रशासन केंद्र शासित प्रदेश के निवासियों से इसकी वसूली कर रहा है, जो इसके प्रावधानों के तहत आते हैं। जहां तक पंजाब राज्य का संबंध है, उसने इस अधिनियम को निरस्त कर दिया है; और अब पंजाब के क्षेत्रों में, ऐसा कोई कर वसूल नहीं किया जाता है।

(5) जहां तक प्रथम विवाद का संबंध है, यह कोई कठिनाई प्रस्तुत नहीं करता है। यह अधिनियम केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ पर लागू होने से पहले ही लागू था, क्योंकि यह अविभाजित पंजाब का एक अभिन्न अंग था। इसके अलावा, पुनर्गठन अधिनियम की धारा 87 से 90 के संयुक्त पठन से मामला मजबूत होता है। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील वास्तव में, इस विवाद के बारे में गंभीर नहीं थे। इस विवाद को आगे बढ़ाने का उनका मुख्य उद्देश्य दूसरे विवाद को मजबूत करना था।

(6) दूसरा विवाद वास्तविक विवाद है। उसी के समर्थन में तर्क इस प्रकार आगे बढ़ता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पुनर्गठन अधिनियम की धारा 87 से 90 के तहत व्यवसाय कर अधिनियम केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ पर लागू हो गया, लेकिन भारत के संविधान के अनुच्छेद 276 के मद्देनजर इसका कोई उपयोग नहीं होगा; व्यवसायों, व्यापारों, कॉलिंग या रोजगार पर कर लगाने वाला कानून केवल राज्य या नगर पालिका, जिला बोर्ड, स्थानीय बोर्ड या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के लाभ के लिए लगाया जा सकता है। संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ से कर की वसूली भारत संघ की संचित निधि में जाती है, संघ राज्य क्षेत्र की कोई समेकित निधि नहीं है। इसलिए, इस राजस्व का उपयोग केंद्र शासित प्रदेश के उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किए जाने की संभावना है। इस स्थिति में, यह आग्रह किया जाता है कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के लिए अधिनियम की प्रयोज्यता भारत के संविधान के अनुच्छेद 276 से प्रभावित होगी। यह विवादित नहीं है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, संसद को अनुसूची सातवीं की सूची II में उल्लिखित विषयों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है। यह भी स्वीकार किया जाता है कि अधिनियम, जैसा कि कहा गया है, संसद द्वारा पारित माना जाएगा। अधिनियम के विरुद्ध एकमात्र प्रहार पहले से ही उल्लिखित है, अर्थात्, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की कोई समेकित निधि नहीं होने के कारण, व्यवसाय कर अधिनियम की प्रयोज्यता अनुच्छेद 276 द्वारा प्रभावित होगी। दिलचस्प बात यह है कि इस बात पर विवाद नहीं था कि चंडीगढ़ प्रशासन को चलाने का खर्च भारत संघ की संचित निधि से पूरा किया जाता है, जिसमें फंड को लागू कर से प्राप्तियां जमा की जाती हैं। अतः, यह मानना बिल्कुल वैध होगा कि जहां तक चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र का संबंध है, संविधान के अनुच्छेद 266 के तहत समेकित निधि भारत संघ की संचित निधि है।

(7) मामले को देखने का एक और तरीका है। किसी अधिनियम की वैधता को इसे अधिनियमित करने वाले प्राधिकारी की सक्षमता द्वारा समायोजित किया जाना होता है। यह कोई विवाद नहीं है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 को ध्यान में रखते हुए अब भी चंडीगढ़ के क्षेत्र के लिए केंद्रीय संसद द्वारा अधिनियम लागू किया जा सकता है। संसद के लिए यह कहना भी खुला होगा कि वे संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के लाभ के लिए कानून बना रहे हैं। इसके बावजूद, तर्क यह है कि तब भी चूंकि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की समेकित निधि में जमा नहीं किया जाएगा, ऐसा कोई फंड नहीं है, इसलिए अधिनियम अनुच्छेद 276 से प्रभावित होगा। मैं इस तर्क से सहमत नहीं हूँ। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का प्रशासन पुनर्गठन अधिनियम के तहत केंद्र सरकार के पास निहित है; और केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में संसद द्वारा वैध रूप से पारित कानून को केवल इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की कोई समेकित निधि नहीं है। अनुच्छेद 276 कानून लागू करने वाले राज्य या क्षेत्र की संचित निधि में जमा किए जा रहे कर की बात नहीं करता है। इसके अलावा, जब कोई कानून लागू किया जाता है, तो यह स्पष्ट रूप से उस राज्य या क्षेत्र के लाभ के लिए अधिनियमित किया जाता है जिसके लिए इसे अधिनियमित किया जाता है। किसी भी मामले में, उस इरादे को कानून के निर्माताओं को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।

(8) भले ही मैं अपने दृष्टिकोण में गलत हूँ, पुनर्गठन अधिनियम, विशेष रूप से धारा 88 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए कोई अलग परिणाम नहीं होगा। अधिनियम के प्रयोजनों के लिए और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में इसके आवेदन के संबंध में, यह माना जाना चाहिए कि कोई पुनर्गठन नहीं हुआ है। इस प्रावधान को पूरा महत्व दिया जाना चाहिए और यहां तक कि एक अवास्तविक स्थिति को भी वास्तविक माना जाना चाहिए। इस संबंध में *बॉम्बे राज्य बनाम पांडुरंग*<sup>(1)</sup> मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय देखें।

(9) यदि हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 276 की ओर मुड़ते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि अभिव्यक्ति "राज्य या नगर पालिका, जिला बोर्ड के लाभ के लिए कर" है। स्थानीय बोर्ड या अन्य स्थानीय प्राधिकरण "केवल इस बात पर जोर देता है कि राज्य के पास कर लगाने की शक्ति है; इसके लाभ के लिए सभी कर लगाए जाते हैं। अनुच्छेद 276 का उद्देश्य ऐसे करों को संवैधानिक रूप से अमान्य होने से बचाना था; जितना ये कर वास्तव में, आय पर कर हैं; और इसलिए, राज्य विधायी शक्ति के दायरे में नहीं है। केवल संसद को ही आय पर कर लगाने का अधिकार है। इस संबंध में, भारत *कला भंडार लिमिटेड (निजी)* और एक अन्य बनाम *नगरपालिका समिति, धमनगांव*<sup>(2)</sup> मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का संदर्भ दिया जा सकता है, जिसमें भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 142-ए को अधिनियमित करने के लिए राशन योग्य है; और जिस पर अब संविधान का अनुच्छेद 276 टिका हुआ है। इस निर्णय में बहुमत का दृष्टिकोण, जहां तक यह हमारे उद्देश्य से संबंधित है, निम्नानुसार है -

"\*\* भारत सरकार अधिनियम की अनुसूची VTI की सूची I और II के भीतर आने वाली वस्तुओं के संबंध में प्रांतों और केंद्र के विधायी क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से सीमांकित किया गया था और अब संविधान की अनुसूची VII की समान सूचियों के भीतर आने वाले लोगों के लिए व्यवसायों, व्यापारों, कॉलिंग और रोजगार पर कर आय पर कर हैं और इस प्रकार प्रांतीय और अब राज्य सूची से बाहर हैं। वे विशेष रूप से संसद से संबंधित हैं और उससे पहले केंद्रीय विधानमंडल से संबंधित हैं। फिर भी भारत सरकार अधिनियम, 1935 से पहले बड़ी संख्या में अधिनियमित कानूनों द्वारा, स्थानीय सरकारों और स्थानीय अधिकारियों को ऐसी गतिविधियों पर कर लगाने की शक्ति के साथ निवेश किया गया था। जाहिर है कि यह भारत सरकार अधिनियम की धारा 100 के साथ संघर्ष में था। जब यह महसूस किया गया, तो ब्रिटिश संसद ने धारा 142-ए लागू की, जो पहले से मौजूद कानूनों द्वारा प्रदत्त शक्ति को बचाती है, लेकिन 31 मार्च, 1939 के बाद देय राशि को 50 रुपये तक सीमित कर देती है। इस धारा को संविधान के अनुच्छेद 276 में इस संशोधन के साथ काफी हद तक पुनः प्रस्तुत किया गया है कि प्रति वर्ष देय ऐसे कर की ऊपरी सीमा 50 रुपये के बजाय 250 रुपये होगी। \* \* \*"

संविधान के अनुच्छेद 276 का उद्देश्य इस प्रावधान के अनुसरण में वसूल किए गए करों को शुल्क में डालना नहीं था। "कर" और "शुल्क" के बीच अंतर सुप्रीम कोर्ट के *आयुक्त, हिंदू धार्मिक बंदोबस्त, मद्रास बनाम श्री शिरूर मठ के श्री लक्ष्मींद्र तीर्थ स्वामीर*<sup>(3)</sup> में लाया गया है। इस निर्णय के अनुसार "कर" और "शुल्क" हैं-

"कानून द्वारा लागू सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा धन का अनिवार्य निष्कासन और प्रदान की गई सेवाओं के लिए भुगतान नहीं है। यह परिभाषा एक कर की आवश्यक विशेषताओं को लागू करने के अन्य रूपों से अलग करती है, जो एक सामान्य अर्थ में, इसके भीतर शामिल हैं। कराधान का सार मजबूरी है, अर्थात्, यह करदाता की सहमति के बिना वैधानिक शक्ति के तहत लगाया जाता है और भुगतान कानून द्वारा लागू किया जाता है। कर की दूसरी विशेषता यह है कि यह कर के भुगतानकर्ता को प्रदान किए जाने वाले किसी भी विशेष लाभ के संदर्भ के बिना सार्वजनिक उद्देश्य के लिए लगाया गया एक अधिरोपण है। यह यह कहते हुए व्यक्त किया जाता है कि कर की लेवी सामान्य राजस्व के प्रयोजनों के लिए है, जो एकत्र होने पर, राज्य के सार्वजनिक राजस्व का हिस्सा बनती है। चूंकि



कर का उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष को कोई विशेष लाभ प्रदान करना नहीं है, इसलिए करदाता और सार्वजनिक प्राधिकरण के बीच 'लेन-देन' का कोई तत्व नहीं है। कराधान की एक और विशेषता यह है कि चूंकि यह आम बोज़ का एक हिस्सा है, इसलिए करदाता पर लगाए गए अधिरोपण की मात्रा आम तौर पर भुगतान करने की उसकी क्षमता पर निर्भर करती है।

"एक शुल्क को आम तौर पर कुछ सरकारी एजेंसियों द्वारा व्यक्तियों को प्रदान की गई विशेष सेवा के लिए शुल्क के रूप में परिभाषित किया जाता है। लगाए गए शुल्क की राशि को सेवा प्रदान करने में सरकार द्वारा किए गए खर्चों पर आधारित माना जाता है, हालांकि कई मामलों में लागतों का मनमाने ढंग से मूल्यांकन किया जाता है। आम तौर पर, शुल्क एक समान होते हैं और भुगतान करने के लिए विभिन्न प्राप्तकर्ताओं की अलग-अलग क्षमताओं का कोई हिसाब नहीं लिया जाता है। ये निस्संदेह कुछ सामान्य विशेषताएं हैं, लेकिन चूंकि विभिन्न प्रकार के शुल्क हो सकते हैं, इसलिए एक परिभाषा तैयार करना संभव नहीं है जो सभी मामलों पर लागू होगा।

(10) अनुच्छेद 276 में ऐसा कोई उपबंध नहीं है कि राज्य या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा इस उपबंध के अनुसरण में एकत्र किए गए कर को उन लोगों के लाभ के लिए व्यय किया जाना चाहिए जो इसका भुगतान करते हैं या उस क्षेत्र के निवासियों के लाभ के लिए जिसमें इसे एकत्र किया जाता है। जाहिर है, सभी करों को एक उद्देश्य के लिए एकत्र किया जाता है - उद्देश्य प्रशासन का संचालन करना और नागरिकों के लिए अन्य लाभकारी उपाय प्रदान करना है। रिटर्न के पैराग्राफ 21(4) में हलफनामे में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस मद में एकत्र किए गए कर का उपयोग केंद्र शासित प्रदेश के लाभ के लिए किया जाता है। इसलिए, भले ही अनुच्छेद 276 पर एक बहुत सीमित और संकीर्ण व्याख्या रखी गई हो, वह भी संतुष्ट है।

(11) इस मामले पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, मैं यह कहने में असमर्थ हूँ कि व्यवसाय कर अधिनियम संविधान के दायरे से बाहर है।

(12) अंतिम विवाद केवल उच्च न्यायालय के कर्मचारियों के मामले में उठता है। उनके विवाद को संदर्भित क्रम में निम्नलिखित तरीके से निपटाया गया है -

"अधिनियम की धारा 7 \*\*\*\*\* एक विशेष विधि प्रदान करता है जिसके द्वारा 'राज्य या केंद्र सरकार के तहत या स्थानीय प्राधिकरण के रोजगार में सेवारत व्यक्तियों' के मामले में वसूली की जा सकती है। उनके मामले में, कर, जो प्रत्येक ऐसे व्यक्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, 'उसकी कुल सकल आय के संदर्भ में निर्धारित तरीके से स्रोत पर काटा जाएगा।' और नियमों के नियम 9 में सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के रोजगार में व्यक्तियों के अलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा कर के भुगतान के तरीके का प्रावधान है। याचिकाकर्ताओं, जो उच्च न्यायालय के कर्मचारी हैं, की ओर से तर्क यह था कि यद्यपि उन्हें राज्य के मामलों के संबंध में सार्वजनिक सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्ति कहा जा सकता है, वे राज्य सरकार के अधीन सेवा नहीं कर रहे हैं और प्रद्युत कुमार बोस बनाम कलकत्ता उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश (4) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा कर रहे हैं। यह आग्रह किया गया था कि "वाक्यांश - भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन सेवारत व्यक्ति" में ऐसे व्यक्तियों का संदर्भ है जिनके संबंध में प्रशासनिक नियंत्रण राष्ट्रपति या राज्यपाल या राजप्रमुख के नाम पर काम करने वाली संबंधित कार्यकारी सरकार में निहित है। उच्च न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को उपरोक्त वाक्यांश के दायरे में नहीं कहा जा सकता है क्योंकि उनके संबंध में, प्रशासनिक नियंत्रण स्पष्ट रूप से मुख्य न्यायाधीश में निहित है, जिनके पास संविधान के तहत, नियुक्ति और हटाने और सेवाओं की शर्तों के लिए नियम बनाने की शक्ति है। उस मामले में, इसमें शामिल मुद्दा यह था कि क्या उच्च न्यायालय के मूल पक्ष के रजिस्ट्रार की बर्खास्तगी के लिए लोक सेवा आयोग के साथ पूर्व परामर्श आवश्यक था, जो आवश्यक होता यदि रजिस्ट्रार को राज्य सरकार के अधीन सेवारत कहा जा सकता था। यह माना

गया था कि रजिस्ट्रार राज्य सरकार के अधीन सेवा नहीं कर रहा था और परिणामस्वरूप ऐसा कोई परामर्श आवश्यक नहीं था। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा यह स्वीकार किया गया था कि यह मामले में केवल एक तकनीकी और बहुत भौतिक बिंदु नहीं था, क्योंकि एक बार जब यह माना जाता है कि वे कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं, तो जिस तरीके से वसूली की जा सकती है, वह केवल अकादमिक हित का है। \* \* \* \*".

(13) मेरी राय में, यह विवाद दो आधारों पर विफल होना चाहिए, अर्थात् :-

(1) वसूली की इस विधि पर प्रारंभिक चरणों में आपत्ति नहीं की गई थी; और कर्मचारी स्रोत पर कटौती का सामना कर रहे हैं। वसूली की विधि उन्हें संपत्ति के किसी भी अधिकार से वंचित नहीं करती है। कर का भुगतान करना होगा। या तो इसका भुगतान किया जाता है, जैसा कि नियम 9 में प्रदान किया गया है; या इसका भुगतान किया जाता है, जैसा कि नियम 10 और 11 में प्रदान किया गया है। बाद के दो नियम स्रोत पर कटौती से संबंधित हैं और उन व्यक्तियों पर लागू होते हैं, जो अधिनियम की धारा 7 द्वारा कवर किए जाते हैं;

और

(2) यह निर्णय, जिसमें अधीनस्थ न्यायिक को राज्य के अधीन सेवा नहीं करने के लिए माना गया था, एक अलग संदर्भ में प्रस्तुत किया गया था। किसी कर्मचारी को राज्य या संघ के मामलों के संबंध में सेवा नहीं करने के रूप में कल्पना करना संभव नहीं है, जैसा भी मामला हो। इंडिशिया, चाहे वह सेवारत है या नहीं, उस स्रोत द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जिससे वह अपना वेतन प्राप्त करता है। यदि वह संघ की संचित निधि से अपना वेतन प्राप्त करता है, तो वह संघ के मामलों के संबंध में सेवा कर रहा है; और यदि वह इसे राज्य की संचित निधि से प्राप्त करता है, तो वह राज्य के मामलों के संबंध में बचत कर रहा है।

इसलिए, यह कहना सही नहीं होगा कि उच्च न्यायालय के कर्मचारी धारा 7 में उल्लिखित श्रेणी के अलावा किसी अन्य श्रेणी में आते हैं। मैं हरबंस सिंह, जे. द्वारा संदर्भित आदेश में व्यक्त किए गए विचार से पूरी तरह सहमत हूँ कि यह मामला वास्तव में अकादमिक है और इसका कोई व्यावहारिक परिणाम नहीं है। अतः, मैं इस तर्क को भी अस्वीकार करता हूँ।

(14) ऊपर दर्ज कारणों के लिए, इन याचिकाओं को विफल होना चाहिए; और तदनुसार खारिज कर दिया जाता है। लेकिन लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

संधावालिया, जे. - मुझे अपने विद्वान भाई महाजन, जे द्वारा प्रस्तावित निर्णय को जारी करने का विशेषाधिकार है और मैं उनसे सहमत हूँ कि याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाए गए तीन तर्कों में से पहला प्रस्तावित फैसले में दर्ज कारणों के लिए विफल होना चाहिए। मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि वर्तमान मामला 'कर' और 'शुल्क' के बीच अब अच्छी तरह से स्थापित अंतर को नहीं बदलता है और वास्तव में यह अंतर इसमें शामिल मुद्दों के लिए जर्मन प्रतीत नहीं होता है। तथापि, पंजाब व्यवसाय, व्यापार, कॉलिंग और रोजगार कराधान अधिनियम, 1956 (जिसे बाद में पेशा कर अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) के अनुच्छेद 276 के साथ संघर्ष के कारण इसके महत्व के महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में, मैं बहुत सम्मान के साथ, अपने विद्वान भाई द्वारा दिए गए निष्कर्ष से अलग हूँ।

(16) महाजन, जे के निर्णय में तथ्य पूरी तरह से दिखाई देते हैं और उसी आधार को फिर से पार करना अनावश्यक है। हमारे समक्ष उठाए गए विवाद प्राथमिक रूप से कानूनी हैं और यह ध्यान देने के लिए पर्याप्त हो सकता है कि आक्षेपित अधिनियम 1956 में तत्कालीन पंजाब राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित किया गया था। इसकी प्रस्तावना जो संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के संबंध में भी असंशोधित है, निम्नानुसार है-

"पंजाब राज्य के राजस्व के लाभ के लिए व्यवसायों, व्यापारों, कॉलिंग और रोजगार पर कर लगाने के लिए एक अधिनियम।

इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत 6,000 रुपये से अधिक की कुल सकल आय से लेकर 20,000 रुपये प्रति वर्ष से अधिक की कुल सकल आय पर एक श्रेणीबद्ध कर लगाया गया था। कर की मात्रा 120 रुपये से अधिकतम 250 रुपये तक की आय के अनुसार भिन्न होती है। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के संगत उपबंधों और उसके अंतर्गत जारी अधिसूचना के द्वारा यह अधिनियम पूर्ववर्ती पंजाब राज्य के पुनर्गठन के समय 1 नवम्बर, 1966 को संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ पर लागू किया गया। कर के तहत अधिकृत वसूली याचिकाकर्ताओं से की जानी थी। यह ध्यान देने योग्य है कि जहां तक मूल अधिनियम का संबंध है, यह निकटवर्ती पंजाब राज्य में निरस्त हो गया है। इस संदर्भ में याचिकाकर्ताओं की ओर से प्राथमिक तर्क यह उठाया गया है कि 1 नवंबर, 1966 से केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ पर लागू किया गया पेशा कर अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 276 के साथ सीधे टकराव में आ गया है और इसलिए यह कानून के दायरे में आता है। इसलिए निम्नलिखित विवाद हमारे समक्ष उठाया गया था -

"यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 276 के मद्देनजर केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के गठन की तारीख से संविधान के दायरे से बाहर हो गया है, और इसलिए, व्यापार, कॉलिंग या व्यवसायों में लगे व्यक्तियों पर कोई कर नहीं लगाया जा सकता है।

मेरे विचार से उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर संविधान के तीन उपबंधों, अर्थात् के प्रकाश में तैयार किया जाना चाहिए। सातवीं अनुसूची की सूची 1 के अनुच्छेद 276 और प्रविष्टि संख्या 82 और उक्त अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 60। संदर्भ की सुविधा के लिए इन प्रावधानों को पहले निर्धारित किया जा सकता है -

"अनुच्छेद 246 में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य के विधान-मंडल का कोई भी कानून राज्य के लाभ के लिए या उसमें किसी नगरपालिका, जिला बोर्ड, स्थानीय बोर्ड या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के व्यवसायों, व्यापारों, कॉलिंग या रोजगार के संबंध में करों से संबंधित नहीं होगा, इस आधार पर अमान्य होगा कि यह आय पर कर से संबंधित है।

(2) किसी एक व्यक्ति के संबंध में राज्य या राज्य में किसी एक नगरपालिका, जिला बोर्ड, स्थानीय बोर्ड या अन्य स्थानीय प्राधिकरण को व्यवसायों, व्यापारों, कॉलिंग और रोजगारों पर करों के रूप में देय कुल राशि ढाई सौ रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी;

बशर्ते कि\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 82 (सूची I) कृषि आय के अलावा अन्य आय पर कर।

सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 60 (सूची 2) व्यवसायों, व्यापारों, कॉलिंग और रोजगार पर कर।

(17) मैं इस निर्णय पर बोझ डालने से बचना चाहता था, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उपर्युक्त प्रावधानों के इतिहास का एक संक्षिप्त संदर्भ उनके सही अर्थ और महत्व को समझने के लिए अपरिहार्य है। ये तीनों भारत सरकार अधिनियम, 1935 के संगत प्रावधानों से लिए गए हैं और हमें उनकी उत्पत्ति का पता लगाने के लिए आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि मूल रूप से अधिनियमित किया गया था, भारत सरकार अधिनियम की सातवीं अनुसूची में निम्नलिखित प्रविष्टियां शामिल हैं -

"कृषि आय के अलावा अन्य आय पर कर (प्रविष्टि 54 सूची I); कृषि आय पर कर (प्रविष्टि 41, सूची II); व्यवसायों, व्यापारों, कॉलिंग और रोजगार पर कर (सूची II की प्रविष्टि 46)।

अधिनियम में इन विधायी प्रविष्टियों को पारस्परिक रूप से अनन्य बनाने का इरादा था। हालांकि, सूची II की प्रविष्टि 46 में असीमित शक्ति का लाभ उठाते हुए, संयुक्त प्रांत सरकार ने प्रांत में अर्जित 250 रुपये और उससे अधिक के सभी वेतनों पर रोजगार कर लगाने का प्रस्ताव रखा, चाहे प्रांत में या उसके बाहर प्राप्त या प्राप्य हो। यह रोजगार कर वास्तव में छद्म रूप से एक आयकर था। इस स्थिति और इसी तरह की जटिलताओं का सामना करते हुए, ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम, 1935 में धारा 142-ए को शामिल किया और सूची II की प्रविष्टि 46 में संशोधन करके इसे धारा 242-ए के अधीन कर दिया। यह ध्यान देने योग्य है कि आर्कटिक 276 काफी हद तक भारत सरकार अधिनियम की धारा 142-ए के समान है, सिवाय इसमें प्रदान की गई अधिकतम राशि को छोड़कर। इसी प्रकार संविधान की सूची I की प्रविष्टि 82 और सूची II की प्रविष्टि 60 भारत सरकार अधिनियम की संगत प्रविष्टियों के अनुरूप है।

(18) उपर्युक्त से ऐसा प्रतीत होता है कि सूची I के अनुच्छेद 276 और प्रविष्टि 82 और सूची II की प्रविष्टि 60 को अलग-अलग प्राधिकरणों द्वारा एक ही हाथ में एक ही आय के कई करों के खिलाफ कुछ सुरक्षा उपायों को सुरक्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। किसी भी मामले में इस तरह के दोहरे कराधान की घटना और मात्रा दोनों को सीमित दायरे में रखने का प्रयास किया जाता है। यह स्पष्ट है कि संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I और II कराधान की शक्तियों से बचते हैं और भारत संघ और राज्यों के लिए कराधान के पर्याप्त स्रोतों को आवंटित करने के आधार पर आगे बढ़ते हैं, जिसका उद्देश्य दोनों के बीच परस्पर विरोधी या प्रतिस्पर्धी कर शक्तियों की समस्याओं को सीमित करना है। कराधान के संबंध में विधायी सूचियों की यह योजना संविधान द्वारा भारत सरकार अधिनियम, 1935 से उधार ली गई है।

(19) सूची-I की प्रविष्टि 82 में यह स्पष्ट किया गया है कि कृषि आय के अलावा अन्य आय पर केवल संसद ही कर लगाने की हकदार है। राज्य विधानमंडल संविधान के अनुच्छेद 276 द्वारा लगाए गए संकीर्ण दायरे के भीतर के अलावा उस क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं कर सकता है। यह अनुच्छेद अपवाद की प्रकृति का होने के कारण (और उस विषय के विरुद्ध, जिसे कई कराधानों से बचाने की मांग की गई है) कड़ाई से समझा जाना चाहिए और इसमें रखी गई सभी अपेक्षित शर्तों को पूरी तरह से संतुष्ट किया जाना चाहिए, इससे पहले कि राज्य विधायिका भी परेशान कर-प्रार्थना की समान आय पर कर लगाने के क्षेत्र में प्रवेश करे।

(20) संविधान के अनुच्छेद 276 की भाषा तीन स्पष्ट सीमाओं को स्पष्ट करती है। पहली सीमा कराधान के विषय के संबंध में है और इसमें यह निर्धारित किया गया है कि बचाए जाने वाले प्रासंगिक कर को व्यवसायों, व्यापारों, कॉलिंग और रोजगारों के संबंध में होना चाहिए। दूसरे, कर की मात्रा पर एक सीमा लगाई गई है और यह निर्धारित किया गया है कि ऐसा कर प्रति वर्ष 250 रुपये से अधिक नहीं होगा। तीसरी सीमा जिसके साथ हम सीधे संबंधित हैं, इस तरह के कर लगाने के उद्देश्य से संबंधित है, अर्थात्, यह राज्य या नगर पालिका, जिला बोर्ड, स्थानीय बोर्ड या अन्य

स्थानीय प्राधिकरण के आर्थिक लाभ के लिए एक कर होना चाहिए। यदि ये तीनों शर्तें पूरी हो जाती हैं तो केवल एक राज्य द्वारा लगाई गई आय पर कर अनुच्छेद 276 की स्पष्ट शर्तों द्वारा अमान्य होने से बचाया जाता है। संक्षेप में, इसलिए वर्तमान मामले में व्यापक मुद्दा यह है कि क्या ये सभी तीन योग्यताएं, सीमाएं या परीक्षण संतुष्ट हैं। यदि वे कर लगाने वाले कानून को बचा रहे हैं, यदि वे नहीं हैं, तो अनुच्छेद 276 के साथ संघर्ष के कारण अधिनियम असंवैधानिकता से दागदार है।

(21) हम उपर्युक्त तीन मानदंडों को लागू करने के लिए आधार साफ कर सकते हैं। प्रतिवादियों की ओर से हमारे समक्ष यह पूरी तरह से स्वीकार किया जाता है (जैसा कि मेरे विद्वान भाई हरबंस सिंह, जे के फैसले में देखा गया है कि व्यवसाय कर अधिनियम के तहत लगाया गया कर आय पर कर के रूप में है। यहां तक कि कानून का संदर्भ देते हुए, जिस अनुपात में इसे कुल सकल आय पर लगाया जाता है और इसे लगाने का तरीका शायद ही इस स्कोर पर कोई संदेह छोड़ता है। इसलिए, हम स्वीकृत आधार पर आगे बढ़ते हैं कि व्यवसाय कर अधिनियम आय पर कर लगाता है।

(22) अनुच्छेद 276 के उपबंधों के संदर्भ से पता चलता है कि उपर्युक्त मानदंडों में से दो स्पष्ट रूप से संतुष्ट हैं। निस्संदेह यह अधिनियम व्यवसायों, व्यापारों, कॉलिंग या रोजगार के संबंध में एक कर है और इस संबंध में अनुच्छेद 276 की आवश्यकता के चार कोनों के भीतर है। यह मात्रा की सीमा को भी संतुष्ट करता है क्योंकि इसमें लगाए गए कर की अधिकतम राशि 250 रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं है। यह समान रूप से स्पष्ट है कि यह अधिनियम नगर पालिका, जिला बोर्ड, स्थानीय बोर्ड या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के लाभ के लिए कर नहीं लगाता है। जैसा कि उत्तरदाताओं द्वारा स्वीकार किया गया है, कर कथित तौर पर एक राज्य के लाभ के लिए लगाया जा रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इस अधिनियम द्वारा लगाई गई आय पर कर केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के राजस्व के लाभ के लिए है। अनुच्छेद 276 की भाषा का प्रयोग करने के लिए, क्या यह अधिनियम 'राज्य के लाभ के लिए करों से संबंधित राज्य के विधानमंडल का कानून' है। इसलिए, अनुच्छेद 276 के ये शब्द उस प्रश्न का सुराग हैं जो वर्तमान मामले में निर्धारण के लिए उठता है। इसलिए, ये शब्द एक करीबी परीक्षा और विश्लेषण के लायक हैं। मेरे विचार से इनका अर्थ सामान्यतः राज्य के लाभ के लिए प्रत्येक कानून से संबंधित नहीं माना जाना चाहिए। वास्तव में, वे करों से संबंधित एक कानून का उल्लेख करते हैं जो बदले में राज्य के लाभ के लिए है। इसलिए, लाभ एक सामान्य लाभ नहीं है जिसे किसी भी कानून द्वारा अर्जित माना जा सकता है, बल्कि विशेष कर लगाने वाले राज्य को प्राप्त होने वाले राजस्व के रूप में एक लाभ है। इन शब्दों पर रखी जाने वाली यह व्याख्या पेटेंट से कहीं अधिक है क्योंकि जब अनुच्छेद 276 (1) के प्रावधानों को स्पष्ट रूप से पढ़ा जाता है, तो प्रासंगिक कर या तो राज्य या नगर पालिका, जिला बोर्ड, स्थानीय बोर्ड या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के लाभ के लिए हो सकता है। जबकि आम तौर पर जैसा कि मेरे विद्वान भाई महाजन, जे द्वारा देखा गया है, यह अच्छी तरह से कहा जा सकता है कि सभी कानून राज्य या उस क्षेत्र के लाभ के लिए बनाए जाते हैं जिसके लिए वे अधिनियमित किए जाते हैं, लेकिन क्या यह कहा जा सकता है कि सभी कानून एक स्थानीय प्राधिकरण के लाभ के लिए भी हैं? इसका उत्तर नकारात्मक होना चाहिए क्योंकि एक राज्य कानून एक स्थानीय प्राधिकरण के नुकसान के लिए हो सकता है क्योंकि उदाहरण के लिए यह इसके उन्मूलन का प्रावधान भी कर सकता है। अतः लाभ शब्द का प्रत्यक्ष और अटूट संबंध 'करों' से है, अर्थात् अनुच्छेद में राज्य को ठोस वित्तीय और राजस्व लाभ या स्थानीय प्राधिकरण के विकल्प के रूप में देखा गया है, न कि एक सामान्य लाभ जिसे सभी विधानों से प्राप्त माना जा सकता है। यह तब और अधिक हो जाता है जब फैसले के पहले भाग में उद्धृत प्रस्तावना का संदर्भ दिया जाता है जो स्पष्ट रूप से संदर्भित करता है कि अधिनियम "पंजाब राज्य के राजस्व के लाभ के लिए" है। इसी प्रकार, इस अधिनियमन के उद्देश्य और कारण, जिन्हें नीचे उद्धृत किया गया है, में यह उल्लेख किया गया है कि बढ़े हुए व्यय आदि को पूरा करने के लिए राज्य के संसाधनों में वृद्धि करने की दृष्टि से कर लगाया जा रहा है।

(23) अतः यह मुद्दा इस तक सीमित हो जाता है कि क्या अधिनियम और उसके अधीन लगाए गए कर संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ को कोई प्रत्यक्ष वित्तीय लाभ प्रदान करते हैं? यदि ऐसा होता है; यह अनुच्छेद 276 के अनुरूप होगा और यदि ऐसा नहीं होता है, तो यह स्पष्ट रूप से इसका उल्लंघन होगा।

(24) इसमें कोई विवाद नहीं है कि संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 2(58) के मद्देनजर एक राज्य है। फिर भी अनुच्छेद 239 से 241 युक्त संविधान का भाग VIII इस ओर आकर्षित होगा। प्रशासन और राजस्व के प्रयोजनों के लिए, हालांकि, भारत में केंद्र शासित प्रदेश अब केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम, 1963 के आधार पर दो वर्गों के भीतर आते हैं। उक्त अधिनियम द्वारा- धारा 2(ज) के तहत, संघ राज्य क्षेत्र से हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन देव और पांडिचेरी में से कोई भी संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है। इसी अधिनियम की धारा 47 द्वारा उपर्युक्त संघ राज्य क्षेत्रों की संचित निधियों के सृजन के लिए एक प्रावधान किया गया है जिसमें भारत सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक द्वारा किसी संघ राज्य क्षेत्र में प्राप्त सभी राजस्व जमा किए जाएंगे। उक्त धारा की उपधारा (2) और (3) द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि सभी संघ राज्य क्षेत्रों की संचित निधियों में से धनराशि का विनियोजन केवल इस अधिनियम में उपबंधित प्रयोजनों के अनुसार और प्रयोजनों के लिए और इस अधिनियम में उपबंधित रीति से किया जा सकता है और इसके अतिरिक्त संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि की अभिरक्षा उक्त संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक द्वारा उसके अनुमोदन से बनाए गए नियमों द्वारा विनियमित की जाएगी। अध्यक्ष उक्त अधिनियम की धारा, 3 द्वारा, पूर्व में निर्दिष्ट धारा 2 (एच) में उल्लिखित संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विधान सभाओं के निर्माण के लिए भी प्रावधान किया गया है। यह सच है कि संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र सरकार अधिनियम, 1963 के दायरे में नहीं आता है और उपर्युक्त अधिनियम की धारा 47 में किए गए प्रावधान के अनुसार कोई विधायिका या अपनी कोई समेकित निधि नहीं है। नतीजतन, हमने प्रतिवादियों के वकील से पूछा था और जवाब में यह स्वीकार किया गया था कि केंद्र शासित प्रदेश का अपना कोई स्वतंत्र राजस्व नहीं है। यह भी स्वीकार किया जाता है कि सभी कर (व्यवसाय कर अधिनियम के तहत लगाए गए कर सहित), राजस्व, ऋण और इसकी ओर से प्राप्त सभी धन भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 के तहत बनाई गई भारत की समेकित निधि में जमा किए जाते हैं और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ से संबंधित कोई अलग खाता या निधि नहीं है जिसमें ये राशि भी जमा की जा सकती है। इसलिए, हालांकि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के पास सामान्य खंड अधिनियम की धारा 2 (58) के मद्देनजर एक कानूनी पहचान है, हालांकि, इसकी अपनी कोई वित्तीय पहचान नहीं है।

(25) व्यवसाय कर अधिनियम द्वारा अधिनियमित कानून के तहत लगाए गए कर की आय के बारे में जो स्पष्ट स्थिति उभरती है, वह यह है कि यह पूरी राशि सीधे भारत की संचित निधि में जाती है। इसका कोई भी हिस्सा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के किसी अलग खजाने में नहीं जाता है। यह स्वीकार किया जाता है कि इस राशि की कोई अलग पहचान या खाता नहीं रखा जाता है जब इसे भारत की संचित निधि में जमा किया जाता है। एक बार जब यह भारत की संचित निधि में जमा हो जाता है, तो इसकी अभिरक्षा, नियंत्रण और विनियोग भारत संघ में निहित होता है। यह अनुच्छेद 266(3) के प्रावधानों से पूरी तरह से स्पष्ट है जो निम्नानुसार है -

"भारत की संचित निधि या किसी राज्य की संचित निधि में से कोई भी धन कानून के अनुसार और इस संविधान में प्रदान किए गए उद्देश्यों और तरीके के अलावा विनियोजित नहीं किया जाएगा।

उपरोक्त प्रावधान को संविधान के अनुच्छेद 114 और 115 के आलोक में पढ़ा जाना चाहिए जो विनियोग विधेयकों और अनुपूरक, अतिरिक्त या अतिरिक्त अनुदानों का प्रावधान करता है, जिसके तहत उपरोक्त निधि से राशि वापस ली जा सकती है। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्र शासित

प्रदेश चंडीगढ़ के लाभ के लिए कर होने से दूर, यह स्पष्ट रूप से भारत संघ के लाभ के लिए लगाया जा रहा है। हमने प्रतिवादियों के विद्वान वकील से दो प्रश्न पूछे थे, अर्थात्, क्या अधिनियम के तहत लगाए गए कर को भारत की संचित निधि में जमा किए जाने के बाद केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के पास उस पर कोई नियंत्रण या विनियोग का अधिकार है। प्रतिवादियों के विद्वान वकील को काफी हद तक स्वीकार करना पड़ा कि केंद्र शासित प्रदेश के पास फंड पर ऐसी कोई शक्ति या नियंत्रण नहीं था। इस मुद्दे के बारे में कि क्या केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासन के लिए खर्च किया गया धन किसी भी तरह से उसी के भीतर एकत्र किए गए करों के अनुपात या संबंधित था, उत्तर समान रूप से स्पष्ट नकारात्मक था। यह स्वीकार किया गया है कि केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन और अन्य उद्देश्यों पर खर्च की गई राशि भारत संघ से अनुग्रह अनुदान के रूप में आती है और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ से एकत्र किए गए राजस्व या करों के लिए इन अनुदानों का कोई कल्पनीय संबंध, साठगांठ या अनुपात नहीं है। इसी तरह इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ न तो पूरी तरह से और न ही एक हिस्से का दावा कर सकता है और न ही व्यवसाय कर अधिनियम के तहत लगाए गए कर के किसी भी अनुपात का दावा कर सकता है।

(26) संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के राजस्व के लाभ के लिए कर के बिंदु पर दो और परीक्षण भी देखे जा सकते हैं। सकारात्मक रूप से बोलते हुए, इस बात से इनकार नहीं किया जाता है कि यदि व्यवसाय कर में प्रदान किए गए कर की दरों को इसके निचले स्तरों में बढ़ाया जाता है या उससे राजस्व बढ़ाया जाता है, तो केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को इससे कोई प्रत्यक्ष आनुपातिक लाभ प्राप्त नहीं होगा। नकारात्मक रूप से, यदि कर को असंवैधानिक के रूप में निरस्त कर दिया जाता है या इसे निरस्त कर दिया जाता है और एकत्र नहीं किया जाता है, तो यह फिर से केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रयोजनों के लिए भारत संघ द्वारा किए गए वित्त के आवंटन को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेगा।

(27) इन सबके आलोक में, क्या यह संभवतः कहा जा सकता है कि आक्षेपित अधिनियम के तहत लगाया गया कर केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के राजस्व के लाभ के लिए है? ऐसा शायद ही तब हो सकता है जब यह वस्तुतः स्वीकार किया जाए कि केंद्र शासित प्रदेश का अपना कोई राजस्व नहीं है और न ही कोई अलग खजाना है जिसमें इस तरह का कर जा सके। इसके विपरीत कर भारत संघ के खजाने में जाता है और पूरी तरह से इसके नियंत्रण में है। आखिर एक टैक्स का फायदा क्या होता है। सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए एक "कर" "पैसा" है और यह निर्विवाद है कि कर या धन का लाभ या तो उस व्यक्ति को जाता है जिसके खजाने या जेब में पैसा जाता है या जिसके पास इसे हड़पने का नियंत्रण या शक्ति है। बौवियर के कानूनी शब्दकोश में "लाभ" शब्द को 'लाभ, फल या लाभ' के रूप में परिभाषित किया गया है। क्या केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को इस कर की आय का कोई प्रत्यक्ष लाभ या फल या लाभ है? जवाब मुझे स्पष्ट रूप से नकारात्मक प्रतीत होता है। इसलिए किसी राज्य अर्थात् संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ द्वारा आय पर कर लगाने के लिए वर्तमान मामले में यह मूलभूत शर्त नहीं है। इस तरह के अधिरोपण को केवल तभी बचाया जा सकता है जब यह अनुच्छेद 276 की इस आवश्यक योग्यता को पूरा करता है। परिणामस्वरूप इसे उक्त अनुच्छेद द्वारा बचाया नहीं गया है और इसके प्रावधानों के अनुरूप न होना स्पष्ट रूप से इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

(28) हमारे समक्ष यह तर्क दिया गया था कि 1956 में अधिनियमित किया गया व्यवसाय कर अधिनियम पूर्ववर्ती पंजाब राज्य में कानून का एक पूरी तरह से वैध टुकड़ा था और इसके बाद के विभाजन से यह प्रावधान असंवैधानिक नहीं हो जाएगा। मेरे विचार से विवाद कायम नहीं रह सकता। अधिनियम की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह पूर्ववर्ती पंजाब राज्य के राजस्व के लाभ के लिए उक्त समय लगाया जा रहा था और इसमें कोई विवाद नहीं है कि ऐसा था। विधेयक को अधिनियमित करने के उद्देश्य और कारण स्पष्ट रूप से निम्नानुसार बताए गए हैं -

विकास पर बड़े हुए खर्च को पूरा करने के लिए राज्य के संसाधनों को बढ़ाने की दृष्टि से, सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष से उच्च आय समूहों पर पेशेवर कर लगाने का निर्णय लिया है, जो बड़े पैमाने पर समुदाय की भलाई के लिए अपनी आय का एक हिस्सा भुगतान करने में सक्षम हैं।

जब तक कर की आय कर लगाने वाले राज्य के राजस्व में चली जाती थी, तब तक अनुच्छेद 276 की शर्तें पूरी तरह से संतुष्ट रहीं और अधिनियम लागू रहा। हालांकि, उन शर्तों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया जा रहा है जब इसे केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में लगाया जा रहा है और उक्त क्षेत्र के राजस्व के लाभ के लिए दूर-दूर तक जिम्मेदार नहीं ठहराया जा रहा है। यह, जैसा कि मैंने ऊपर कहा है, अनुच्छेद 276 का स्पष्ट उल्लंघन है। मुझे यह स्वयंसिद्ध प्रतीत होता है कि यदि यह अधिनियम संविधान के इस प्रावधान के विपरीत आता है, तो इसे निरस्त कर दिया जाना चाहिए। एक बार ऐसा हो जाने के बाद, कोई अन्य अधिनियम, कानूनी कल्पना या संसद या राज्य के किसी अन्य अधिनियम में समझा गया प्रावधान इसे असंवैधानिकता के दाग से नहीं बचा सकता है। अब यह सब समझ से परे है कि संविधान के खिलाफ सभी कानून शून्य हैं। इसलिए, अपने विद्वान भाई के प्रति सम्मान के साथ, मुझे नहीं लगता कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम की धारा 88 या कोई अन्य प्रावधान इस अधिनियम को असंवैधानिकता के दाग से बचा सकता है यदि यह अनुच्छेद 276 का उल्लंघन है। मेरे विचार से धारा 88 ऐसी कोई कानूनी कल्पना नहीं बनाती है कि राज्य का पुनर्गठन नहीं माना जाएगा। यह कानूनों की क्षेत्रीय सीमा के संदर्भ में केवल यह कहता है कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के भाग दो के प्रावधानों को उन क्षेत्रों में कोई बदलाव करने वाला नहीं माना जाएगा, जिन पर नियत दिन से ठीक पहले लागू कोई कानून विस्तारित या लागू होता है।

(29) उत्तरदाताओं की ओर से अंतिम तर्क को भी संक्षेप में देखा जा सकता है। यह तर्क दिया गया था कि केवल इसलिए कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के पास अपनी कोई समेकित निधि नहीं है, व्यवसाय कर असंवैधानिक नहीं होगा। विवाद अच्छी तरह से आधारित नहीं है। निस्संदेह समेकित निधि में कोई जादू नहीं है। यह निधि केवल राज्य की ओर से एकत्र किए गए धन को हड़पने के लिए अभिरक्षा, नियंत्रण और शक्ति दिखाने के लिए एक संकेतक है। इस तरह की शक्ति को अन्य इंडिशिया द्वारा भी दिखाया जा सकता है। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, हालांकि, यह स्वीकार किया जाता है कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के पास कोई अन्य अलग फंड या खजाना या खाता नहीं है जिसमें एकत्र किए गए राजस्व को जमा किया जा सके। यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि हिरासत नियंत्रण और क्षेत्र में एकत्र किए गए राजस्व या धन को हड़पने की शक्ति स्थानीय इकाई में निहित है जो चंडीगढ़ का केंद्र शासित प्रदेश है। यदि ऐसा होता तो उत्तरदाताओं के लिए यह दिखाना संभव हो सकता था कि कर केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के लाभ के लिए लगाया जा रहा था। जैसा कि इस निर्णय के पहले भाग में देखा गया था, मुद्दा यह है कि क्या समेकित निधि या किसी भी खाते के अभाव में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की भारत संघ से अपने हिस्से की एक अलग राजकोषीय पहचान है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के भीतर एकत्र राजस्व जा सकता है। यह स्पष्ट है कि इसमें एकत्र किया गया राजस्व सीधे भारत संघ में निहित है, जिसके पास इसके विनियोजन की शक्ति है। जब तक ऐसा है, अनुच्छेद 276 में निर्धारित शर्त को या तो राज्य क्षेत्र में कानून के विस्तार से संतुष्ट नहीं किया जा सकता है, या यहां तक कि उसी उद्देश्य के लिए केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की ओर से संसद का एक अधिनियम पारित करके भी संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च शर्त अनुच्छेद 276 की आवश्यकता की संतुष्टि है कि कर लगाने वाले राज्य के राजस्व के लाभ के लिए कर होना चाहिए और जब तक "ऐसा नहीं किया जाता है" असंवैधानिकता की बुराई को ऐसे कानून से जोड़ना जारी रखना चाहिए।

(30) इस संदर्भ में मैं इस बात पर ध्यान देना चाहूंगा कि हमारे सामने जो बात दृढ़ निश्चय के लिए उठी थी, उस पर प्रत्यक्ष अधिकार का पूर्ण अभाव है। न तो याचिकाकर्ताओं की ओर से और न ही प्रतिवादियों की ओर से उपरोक्त मुद्दे पर कोई सीधा संबंध रखने वाले किसी भी मामले के कानून का हवाला दिया गया है। फिर भी उत्तरदाताओं के विद्वान वकील के प्रति निष्पक्षता से मैं उल्लेख कर सकता हूँ कि उन्होंने



भारत कला भंडार लिमिटेड (निजी और अन्य बनाम नगरपालिका समिति, भामनगांव (2) और आयुक्त हिंदू धार्मिक बंदोबस्त, मद्रास बनाम श्री शिरूर मठ के श्री लक्ष्मींद्र तीर्थ स्वामीर (3) पर भरोसा करने की मांग की। - जिसका संदर्भ मेरे विद्वान भाई महाजन जे ने अपने निर्णय में दिया है। रिलायंस को आई.टी.एम. कन्वियन और अन्य बनाम आयकर अधिकारी, पांडिचेरी और अन्य (5) पर भी रखा गया था। लेकिन उक्त निर्णय का बारीकी से विश्लेषण करने पर मुझे पता चलता है कि न तो तथ्यों और न ही उसके अनुपात का मुद्दे पर कोई प्रभाव पड़ता है।

(31) तीसरा विवाद जो याचिकाकर्ता की ओर से उठाया गया है, वह केवल 1968 की सिविल रिट संख्या 3759 में उत्पन्न होता है, जिसे उच्च न्यायालय के कर्मचारियों द्वारा दायर किया गया है। यह इस प्रकार था:

"यह कि उच्च न्यायालय के कर्मचारी किसी राज्य या किसी स्थानीय प्राधिकरण आदि के तहत सेवा नहीं कर रहे हैं और परिणामस्वरूप व्यवसाय कर अधिनियम की धारा 7 और उक्त अधिनियम के तहत बनाए गए नियम 8 उन पर लागू नहीं होते हैं और यह वसूली उपरोक्त नियमों में प्रदान किए गए अनुसार उनके वेतन बिलों से कटौती से प्रभावी नहीं हो सकती है; और यदि कर वसूली योग्य है तो इसे नियम 9 में दिए गए तरीके से वसूल किया जा सकता है।

दूसरे विवाद पर मैंने ऊपर जो राय दर्ज की है, उसके आलोक में यह मुद्दा पूरी तरह से अकादमिक हो जाता है और इसलिए इसका कोई परिणाम नहीं होता है। इसलिए, मैं इस पर कोई भी राय व्यक्त करने से बचूंगा।

(32) पूर्वगामी चर्चा के आलोक में मैं यह कहूंगा कि पंजाब व्यवसाय, व्यापार, कॉलिंग और रोजगार कराधान अधिनियम, 1956, जैसा कि चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र पर लागू होता है, अनुच्छेद 276 का उल्लंघन है और इसलिए संविधान का उल्लंघन है। ऐसा होने पर दोनों रिट याचिकाएं सफल होनी चाहिए और उन्हें अनुमति दी जानी चाहिए, लेकिन मैं लागत के बारे में कोई आदेश प्रस्तावित नहीं करूंगा।

**न्यायमूर्ति** हरबंस सिंह,—मैं **न्यायमूर्ति** संधावलिया से सहमत हूँ।

पूर्ण पीठ का आदेश

(33) बहुमत से इन याचिकाओं को स्वीकार किया जाता है और पेशेवर कर लगाने को शून्य और शून्य घोषित किया जाता है, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

के.एस.के.

---

(1) ए.आई.आर. 1953 एस.सी. 244.

(2) ए.आई.आर. 1966 एस.सी. 249.

(3) ए.आई.आर. 1954 एस.सी. 282.

(4) ए.आई.आर. 1956 एस.सी. 285.

(5) ए.आई.आर. 1968 एस.सी. 637.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अभिनव गर्ग

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

फ़रीदाबाद, हरियाणा